फ़िलिस्तीन कल और आज

अरब इज़राइल संघर्ष का समाजशास्त्र

डॉ. अज़िज़ुर रहमान आज़मी

फ़िलिस्तीन कल और आज

अरब इज़राइल संघर्ष का समाजशास्त्र

डॉ. अज़ीज़ुर रहमान आज़मी

ISBN: "978-93-87621-57-2"

प्रकाशक: नॉटनल

अनुक्रम

आरम्भ	9
फ़िलिस्तीन का इतिहास और दावे	17
ब्रिटिश जनादेश और फ़िलिस्तीनी समस्या की शुरुआत	27
संयुक्त राष्ट्र विभाजन और अरब-इज़राइल युद्ध	38
फ़िलिस्तीन के लिए फ़िलिस्तीन अरबों का संघर्ष	49
फ़िलिस्तीन आज	57
इज़राइल आजकल	68
उपसंहार	78

फारवर्ड

1967 से ही फ़िलिस्तीन क्षेत्र (occupied territory) इज़राइल के सैन्य नियंत्रण में रहा हैं। आधुनिक इतिहास में इसे लम्बे समय तक किसी क्षेत्र को सैन्य नियंत्रण में बनाये रखने का यह पहला उदाहरण है. इस कब्जे वाले क्षेत्रों में ग़ाज़ा, वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलैम शामिल हैं। ग़ाज़ा पट्टी एक छोटा तटीय क्षेत्र है जो मिस्र की दक्षिण सीमा से लगता है और इस क्षेत्र में लगभग दो मिलियन फिलिस्तीनियों का निवास है। वेस्ट बैंक गुर्दे की फलियों के आकार का क्षेत्र है। यह जॉर्डन नदी के तट के पश्चिम में स्थित है जिसके कारण इसे वेस्ट बैंक या (पश्चिमी किनारा) कहा जाता है. पूर्वी येरुशलैम 1949 की ग्रीन लाइन के फ़िलिस्तीन किनारे पर स्थित है। तीन मिलियन फ़िलिस्तीन वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलैम में रहते हैं।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ब्रिटेन ने मध्य पूर्व में विभिन्न समूहों का समर्थन हासिल करने के लिए कई परस्पर विरोधी समझौते किए। जिसमें सबसे प्रमुख बल्फोरे घोषणा पत्र (Balfour declaration) है. यह एक सार्वजनिक प्रतिज्ञा थी जो यहूदी लोगों के लिए फ़िलिस्तीन में एक राष्ट्रीय आवास की स्थापना" का वादा करता था। 31 अक्टूबर, 1917 को, ब्रिटिश सेनाओं ने फ़िलिस्तीन को ओटोमन तुर्कों से जीत लिया, इस के साथ ही इस क्षेत्र पर 1,400 वर्षों चले आ रहे इस्लामी शासन का अंत हो गया। 1920 से इंग्लैंड ने फ़िलिस्तीन पर अपना 28 साल का शासन शुरू किया। फ़िलिस्तीन में ब्रिटिश जनादेश से पहले, यहूदियों की कुल आबादी लगभग छह प्रतिशत थी। ब्रिटिश जनादेश (British Mandate) ने 1920 और 1930 के दशक में यूरोप से फ़िलिस्तीन में यहूदी अप्रवासन (Immigration) की सुविधा दी। फ़िलिस्तीन में यहूदी आबादी 6 प्रतिशत (1918) से बढ़कर 33 प्रतिशत (1947) हो गई। 1920 से 1946 तक 376,415 यहूदी प्रवासी फ़िलिस्तीन में पहुंचे जिसकी पुष्टि ब्रिटिश रिकॉर्ड से होती है।

द्वितीय विश्व युद्ध (WWII) के अंत के बाद, नवगठित संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐसी योजना का प्रस्ताव दिया जो ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन के 55 प्रतिशत भाग को यहूदी राज्य निर्माण के लिए और 45 प्रतिशत को अरबों के लिए मंजूरी दी जिसमें येरुशलैम को अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में रखा गया। फिलिस्तीनियों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसने बहुत सी ज़मीन छीन ली जो उनके नियंत्रण में थी। उस समय, उनके पास 94% ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन का स्वामित्व था और इसमें 67 प्रतिशत आबादी शामिल थी। इस योजना को कभी भी धरातल पर लागू नहीं किया गया। 14 मई, 1948 को, ब्रिटिश जनादेश की समय सीमा समाप्त से पहले अरब-इज़राइल के पहले युद्ध की शुरुआत हो गयी। ज़ायोनी सैन्य बलों ने कम से कम 750,000 फिलिस्तीनियों को निष्कासित कर दिया और 78% ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। शेष 22 प्रतिशत को वेस्ट बैंक और ग़ाज़ा पट्टी में विभाजित कर दिया गया था। यह लड़ाई जनवरी 1949 तक जारी रही जब इज़राइल और मिस्र, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया के बीच युद्धविराम समझौता हुआ।

जून 1967 के युद्ध के दौरान, इज़राइल ने सभी ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और 300,000 फ़िलिस्तीनियों को उनके घर से निष्कासित कर दिया। इज़राइल ने उत्तर में सीरियाई गोलन हाइट्स और दक्षिण में मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर भी कब्जा कर लिया। 1978 में, मिस्र और इज़राइल ने एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए जिसके कारण इज़राइल को मिस्र के क्षेत्र से हटना पड़ा। इज़राइल ने फ़िलिस्तीन भूमि यहूदी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलैम में कम से कम 250 बस्तियों (130 आधिकारिक और 120 अनौपचारिक) में रहने वाले 600,000 - 750,000 इज़राइली बसा दिया। इज़राइल बसावट पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं जो चौथे जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करते हैं जिसके अनुसार कब्जा वाले क्षेत्र में अपनी आबादी को उस क्षेत्र में स्थानांतरित नहीं किया सकता।

2019 में, डोनाल्ड ट्रम्प की अध्यक्षता में, अमेरिका ने घोषणा की कि फ़िलिस्तीन भूमि पर इज़राइल का कब्ज़ा "जरूरी नहीं कि अवैध" हो। इस तरह का वक्तव्य दशकों से चली आ रही अमेरिकी नीति में एक नाटकीय मोड़ है वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलैम में इज़राइल के निवासियों की आबादी इज़राइल की जनसंख्या की तुलना

में तेज दर से बढ़ रही है। इज़राइल की 6.8 मिलियन यहूदी आबादी का लगभग 10 प्रतिशत इन कब्जे वाले फ़िलिस्तीन क्षेत्रों में रहती है। इज़राइल ने बाहर से आने वाले यहूदी अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान की और उन्हें सरकारी सब्सिडी दी जिससे उनकी रहने की लागत काफी सस्ती हुई। 2020 तक, वेस्ट बैंक में 463,535 यहूदी रिकॉर्डेड बसे हुए थे और पूर्वी येरुशलैम में इनकी संख्या 220,200 है।

2002 के बाद से, इज़राइल ने फ़िलिस्तीन बस्तियों को इज़राइल से अलग करने के लिए एक दीवार का निर्माण कर लिया है जो 700 किलोमीटर से अधिक तक फैली है। इज़राइल का कहना है कि दीवार सुरक्षा उद्देश्यों के लिए है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 1967 की सीमा का पालन करने के बजाय, (जिसे ग्रीन लाइन के रूप में जाना जाता है,) इसकी 85 प्रतिशत दीवार वेस्ट बैंक के भीतर ही आती है। यह फिलीस्तीनियों के आवागमन की स्वतंत्रता अधिकार को सीमित करता है। 140 चौकियों सहित वेस्ट बैंक में 700 से अधिक सड़क बाधाएं हैं। ये चौकियां फ़िलिस्तीन आवागमन को और सीमित करती हैं। इज़राइल के काम करने वाले लगभग 70,000 फ़िलिस्तीन अपने दैनिक आवागमन में इन चौकियों को पार करते हैं।

फ़िलिस्तीन और पड़ोसी देशों में स्थित संयुक्त राष्ट्र के 58 आधिकारिक शिविरों में 1.5 मिलियन फ़िलिस्तीन शरणार्थी रह रहे हैं। कुल मिलाकर, पाँच मिलियन से अधिक पंजीकृत फ़िलिस्तीनी शरणार्थी हैं जो ज्यादातर इन शिविरों के बाहर रहते हैं। फ़िलिस्तीन शरणार्थियों की दुर्दशा दुनिया में सबसे भयावह और अनसुलझे शरणार्थी समस्या है। ओस्लो समझौते पहला फ़िलिस्तीन-इज़राइल शांति समझौते था जिससे फ़िलिस्तीन प्राधिकरण (पीए) का गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ था, एक प्रशासनिक निकाय है जो फिलीस्तीन पर शासन करता है।

प्रोफेसर जावेद इकबाल

हेड ऑफ़ थे डिपार्टमेंट

डिपार्टमेंट ऑफ़ वेस्ट एशियाई एंड नार्थ अफ्रीकन स्टडीज